भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Ref. No.: LIC/SE/2025-26/100

Date: November 07, 2025

To
The Manager
Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai—400001

Scrip Code: 543526

The Manager
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot C/1,
G Block, Bandra Kurla Complex,
Mumbai-400051

Scrip Code: NSE - LICI

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025.

The Board of Directors in its Meeting held on November 06, 2025, inter-alia, has approved the Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial Results ("Financial Results") of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation") for the quarter and half year ended September 30, 2025.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025 are published in the Business Standard (Hindi and English), Navshakti (Marathi) and Free Press Journal (English) in the prescribed format on November 07, 2025. A copy of the Financial Results published in the above-mentioned newspapers are enclosed herewith.

Please take the above information on record and arrange for its dissemination. A copy of this intimation is also being made available on website of the Corporation at www.licindia.in .

Yours faithfully,

For Life Insurance Corporation of India

ANSHUL KUMAR SINGH
Digitally signed by ANSHUL KUMAR SINGH
Date: 2025.11.07 16:38:23 +05'30'

(Anshul Kumar Singh)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

आईपीओ में और सुधार करेगा सेबी

खुशबू तिवारी
मुंबई, 6 नवंबर

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए सुधारों की नई पहल तैयार कर रहा है। इसमें आईपीओ लाने वाली कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखने की प्रक्रिया को सहज बनाना और पेशकश दस्तावेजों में खुलासे की अनिवार्यताओं को औचित्यपूर्ण बनाना शामिल है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

एसबीआई बैंकिंग ऐंड इकनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2025 में पांडेय ने कहा, सेबी आईपीओ पेशकश दस्तावेजों के सारांश वाले हिस्से को सरल बनाने और निवेशकों को उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्हें अलग से उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, आईपीओ से जुड़ी जिन कंपनियों के प्री-आईपीओ शेयर गिरवी रखे गए हैं, उनके लिए प्रक्रिया को सहज बनाया जा रहा है। प्रस्तावित ढांचा यह सुनिश्चित करेगा कि गिरवी रखे गए शेयरों को भुनाने या वापस लेने पर भी लॉक-इन की ज़रूरतें स्वतः लागू हो जाएं, जिससे लिस्टिंग में देरी को रोका जा सके। इन प्रस्तावों पर परामर्श पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे।

नए उपाय सार्वजनिक धन जुटाने को आसान बनाने के मकसद से हाल में की गई पहलों पर आधारित होंगे। इनमें बड़े आईपीओ को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाए गए कदम और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाना शामिल है।

पांडेय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हालिया कदमों की भी सराहना की, जैसे आईपीओ फाइनैंसिंग लिमिट बढ़ाना और रीट्स व इनविट्स यूनिटों के बदले बैंक ऋण में वृद्धि आदि में इजाफा। ऋण के संबंध में उन्होंने कहा कि सेबी कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में कुछ निवेशक श्रेणियों को प्रोत्साहन पर विचार कर रहा है और बॉन्ड डेरिवेटिव शुरू करने के लिए आरबीआई के साथ बातचीत कर रहा है।

नियामक उठाएगा कदम

- आईपीओ पेशकश दस्तावेज़ के सारांश को युक्तिसंगत बनाकर निवेशकों की प्रतिक्रिया ली जाएगी
- आईपीओ लाने वाली कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखने के मानदंडों को सरल बनाया जाएगा ताकि लॉक-इन की अनिवार्यताओं को सुनिश्चित किया जा सके

नियामक कमोडिटी सेगमेंट में सुधारों को भी प्राथमिकता दे रहा है। इनमें बैंक, बीमा और पेंशन फंडों की भागीदारी की संभावना तलाशना शामिल है। पांडेय ने कहा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को गैर-नकद निपटान वाले, गैर-कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंधों में कारोबार की अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सेबी सोशल मीडिया और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों की निगरानी बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, हमारे इन-हाउस सिस्टम हेरफेर वाले ट्रेडिंग पैटर्न का पता लगाने के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हम निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एल्गोरिदम और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के अपने ढांचे को अपडेट करते रहेंगे।

पांडेय ने एसएमई आईपीओ पर कड़ी निगरानी और प्रतिभूति बाजार में विश्वास बढ़ाने के लिए मजबूत अंतर-संस्थागत सहयोग का भी आह्वान किया। इससे पहले, एक्सीलेंस इनेबलर्स के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक शिखर सम्मेलन में सेबी चेयरमैन ने आईपीओ मूल्यांकन से जुड़ी चिंताओं का जवाब दिया।

पांडेय ने कहा, सेबी पारदर्शिता का पक्षधर है। हम मूल्यांकन तय नहीं करते, यह निवेशकों को तय करना है। बाजार को अवसर के आधार पर शेयरों की कीमत तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि खुलासे मजबूत हों और जारी करने वाले दस्तावेज़ में पर्याप्त तुलनात्मक जानकारी हो।

उनकी यह टिप्पणी कुछ स्टार्टअपों और बहुराष्ट्रीय सहायक कंपनियों के महंगे मूल्यांकन और बाजार में उनके सुस्त आगाज की चिंताओं के बीच आई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वतंत्र निदेशक के मानदंडों को पूरा करने में चूक पर पांडेय ने कहा कि सेबी सरकार से नियुक्तियों में तेजी लाने का आग्रह किया।

उन्होंने सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड को वित्तीय मानकों के साथ-साथ संगठनात्मक संस्कृति और आचरण पर नज़र रखने के लिए गवर्नेंस स्कोरकार्ड अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, नियामक ऐसे लोकाचार की तलाश करते हैं, जहां कदाचार दुर्लभ अपवाद हो, न कि व्यवसाय का एक स्वीकार्य जोखिम।

पांडेय ने कहा कि सेबी उद्योग के हितधारकों के साथ परामर्श करके कई नियमों की समीक्षा करेगा ताकि उन्हें सरल और प्रासंगिक बनाया जा सके। उन्होंने कहा, बोर्डों को न केवल वित्तीय जोखिमों बल्कि डेटा नैतिकता, साइबर लचीलेपन और एल्गोरिदम संबंधी निष्पक्षता पर भी नजर रखनी चाहिए। आज गवर्नेंस की व्यवस्था बोर्डरूम से लेकर क्लाउड तक फैली हुई है।

एनएसई कंपनियों में स्वामित्व

घरेलू संस्थागत निवेशकों की एफपीआई पर बढ़त

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 6 नवंबर

प्राइम डेटाबेस के जुटाए आंकड़ों से जाहिर होता है कि सितंबर 2025 तक एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की हिस्सेदारी बढ़कर 18.26 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 76,619 करोड़ रुपये की निकासी के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी 13 साल के निचले स्तर 16.71 प्रतिशत पर रह गई। मार्च 2025 की तिमाही में पहली बार डीआईआई ने एफपीआई को पीछे छोड़ दिया था।

घरेलू संस्थानों में म्युचुअल फंडों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और उनका स्वामित्व लगातार नौवीं तिमाही में बढ़कर 10.93 प्रतिशत के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। सितंबर तिमाही के दौरान म्युचुअल फंडों ने शेयरों में 1.64 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया। कुल मिलाकर डीआईआई का निवेश 2.2 लाख करोड़ रुपये रहा।

जून तिमाही में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी 7.53 प्रतिशत से घटकर 7.43 प्रतिशत रह गई। इसकी वजह उनकी 9,562 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली रही। इस बीच, एचएनआई यानी अमीर निवेशकों की हिस्सेदारी 2.05 प्रतिशत से बढ़कर 2.09 प्रतिशत हो गई।

प्राइम डेटाबेस ग्रुप के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया ने कहा, 'एफपीआई पारंपरिक रूप से भारतीय बाजार में सबसे बड़े गैर-प्रवर्तक शेयरधारक श्रेणी रहे हैं और उनके निवेश निर्णय बाजार की समग्र दिशा को अच्छे-खासे प्रभावित करते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। खुदरा और एचएनआई निवेशकों के साथ-साथ डीआईआई भी अब एक मजबूत जवाबी भूमिका निभा रहे हैं और सितंबर 2025 तक उनकी संयुक्त हिस्सेदारी 27.78 प्रतिशत के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी।' उन्होंने कहा, 'हालांकि एफपीआई एक महत्त्वपूर्ण घटक बने हुए हैं, लेकिन भारतीय पूंजी बाजार पर उनकी पकड़ कम हुई है।'

लगातार तीन तिमाहियों की गिरावट के बाद निजी कंपनियों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी जून के 40.58 प्रतिशत से सितंबर 2025 में बढ़कर 40.7 प्रतिशत हो गई, जबकि शुद्ध बिक्री 24,055 करोड़ रुपये रही। पिछले चार वर्षों में, प्रमोटरों की हिस्सेदारी दिसंबर 2021 के 45.16 प्रतिशत से 446 आधार अंक कम हुई है।

बढ़ी हिस्सेदारी

- घरेलू संस्थानों की हिस्सेदारी बढ़कर 18.26 फीसदी हुई, एफपीआई की हिस्सेदारी 13 साल के निचले स्तर 16.71 प्रतिशत पर
- मार्च 2025 की तिमाही में कंपनियों में स्वामित्व को लेकर पहली बार डीआईआई ने एफपीआई को पीछे छोड़ा था

फिजिक्सवाला को कोर्स की कीमतें बढ़वाने वाले निवेशक नहीं चाहिए

उदिशा श्रीवास्तव और अजिंक्य कावले
नई दिल्ली/मुंबई, 6 नवंबर

एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला (पीडब्ल्यू) ने अपने आईपीओ के लिए 103-109 रुपये का कीमत दायरा तय किया है। आईपीओ 11 नवंबर को खुलकर 13 नवंबर को बंद होगा। कंपनी का लक्ष्य 3,480 करोड़ रुपये जुटाना है। इसकी अधिकांश राशि का इस्तेमाल विस्तार और विकास में किया जाएगा। आईपीओ में 3,100 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि प्रवर्तक 380 करोड़ रुपये तक के शेयरों का ओएफएस होगा।

फिजिक्सवाला का आईपीओ 11 नवंबर को खुलेगा

फिजिक्सवाला के दोनों प्रमोटर अलख पांडेय और प्रतीक बूब ओएफएस के जरिए 190-190 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे। लेकिन कंपनी के निवेशकों में वेस्टब्रिज एआईएफ (6.40 प्रतिशत), हॉर्नबिल कैपिटल पार्टनर्स (4.41 प्रतिशत), जीएसवी वेंचर्स फंड (2.85 प्रतिशत), लाइटस्पीड ऑपर्च्युनिटी फंड (1.79 प्रतिशत) और सेतु एआईएफ ट्रस्ट (1.39 प्रतिशत) शामिल हैं और वे कोई हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं।

पीडब्ल्यू भी गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के जरिये आईपीओ लाने वाली कंपनियों में शामिल हो गई है। 11 नवंबर को अपने आईपीओ से पहले फिजिक्सवाला के सह-संस्थापकों ने कहा कि कंपनी ने मुनाफे और उद्देश्य के बीच विभाजन की रेखा बरकरार रखी है। गुरुवार को प्री-आईपीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अलख पांडे और प्रतीक बूब ने कहा कि कुछ निवेशकों ने उनके प्रमुख पाठ्यक्रमों की कीमतें दोगुनी करने का सुझाव दिया था, लेकिन कंपनी ऐसे निवेशकों या प्रस्तावों पर विचार नहीं कर रही है।

सह-संस्थापक और पूर्णकालिक निदेशक बूब ने कहा, 'हमने अपने प्रमुख बैचों की कीमतें किफायती रखी हैं क्योंकि हम सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहते हैं और शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाना चाहते हैं। हम कभी भी पाठ्यक्रमों की कीमत अचानक नहीं बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इस यात्रा के दौरान कई बार निवेशकों ने हमसे कहा है कि राजस्व को दोगुना करने का सबसे आसान तरीका पाठ्यक्रमों की कीमतें दोगुनी करना है। हम इस प्रकार के निवेशकों को कभी तवज्जो नहीं देते।'

ऑनलाइन निवेश घोटाले पर सेबी ने बढ़ाई सख्ती

सेबी ने ऑनलाइन निवेश घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं और प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन प्रदाताओं से धोखाधड़ी वाली वित्तीय गतिविधियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का आह्वान किया है। नियामक ने प्लेटफॉर्म्स से प्रतिभूति क्षेत्र में विज्ञापनदाताओं के सत्यापन और सेबी -पंजीकृत बिचौलियों के सत्यापित ट्रेडिंग ऐप्स की स्पष्ट लेबलिंग जैसे उपायों को तेजी से लागू करने को कहा है। सेबी ने जनता से संस्थाओं की पंजीकरण स्थिति सत्यापित करने, केवल प्रामाणिक ट्रेडिंग ऐप्स के माध्यम से ही लेनदेन करने और सुरक्षित भुगतान के लिए मान्य यूपीआई हैंडल का उपयोग करने का आग्रह किया है। *बीएस*

चार शेयर एमएससीआई के प्रमुख सूचकांक में शामिल

बीएस संवाददाता
मुंबई, 6 नवंबर

वैश्विक सूचकांक प्रदाता एमएससीआई ने घोषणा की है कि वह फोर्टिस हेल्थकेयर और पेटीएम सहित चार घरेलू कंपनियों को अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड सूचकांक में शामिल करेगा। नुवामा अल्टरनेटिव ऐंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अनुसार इनमें से प्रत्येक कंपनी में 40 करोड़ डॉलर से अधिक का निष्क्रिय निवेश आने की उम्मीद है। गुरुवार को पेटीएम के शेयरों में 4.3 प्रतिशत की तेजी आई जबकि फोर्टिस हेल्थकेयर में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई।

एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होने वाली दो अन्य कंपनियों हैं - जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया और सीमेंस एनर्जी इंडिया। इनमें 35.1 करोड़ डॉलर और 25.2 करोड़ डॉलर का निवेश आने का अनुमान है। इसके विपरीत, टाटा एलेक्सी और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इंडेक्स से हटा दिया गया है, जिससे इनमें 16.2 करोड़ डॉलर और 14.6 करोड़ डॉलर का निवेश बाहर जाने का अनुमान है।

ये बदलाव 24 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद से प्रभावी होंगे। ये बदलाव एमएससीआई के छमाही सूचकांक पुनर्संतुलन का हिस्सा हैं। इसके अलावा, फ्लोट समायोजन के कारण आठ मौजूदा कंपनियों के भारांक में वृद्धि होगी, जबकि सात में कमी आएगी। एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में भारत का भारांक 15.5 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 15.6 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि घटक कंपनियों की संख्या 161 से बढ़कर 163 हो जाएगी।

एमएससीआई के वैश्विक सूचकांकों पर उभरते बाजारों में निवेश के इच्छुक निवेशक व्यापक रूप से नजर रखते हैं जिससे ऐसे सूचकांक संशोधन दुनिया भर में पोर्टफोलियो प्रवाह के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।

एमऐंडएम ने बेची आरबीएल बैंक की पूरी हिस्सेदारी

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (एमऐंडएम) ने गुरुवार को निजी क्षेत्र के लेनदार आरबीएल बैंक में अपनी 3.53 फीसदी हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिये बेच दी। एमऐंडएम ने एक नियामकीय सूचना में कहा, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी ने आरबीएल बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी 678 करोड़ रुपये में बेच दी है, जो निवेश पर 62.5 फीसदी का लाभ दर्शाता है। एमऐंडएम ने जुलाई 2023 में ट्रेजरी निवेश के तौर पर 417 करोड़ रुपये में यह हिस्सेदारी खरीदी थी। *बीएस*

AI in weather forecasting? IMD says not quite there yet

Pilot projects show promise but also reveal gaps, especially in predicting how intense storms and rainfall will be

SANJEEB MUKHERJEE
New Delhi, 6 November

The India Meteorological Department (IMD), which is looking to actively integrate artificial intelligence (AI) models into weather forecasting, has launched small pilot programmes but remains cautious about their accuracy across all aspects of forecasting, IMD Director-General Mrutyunjay Mohapatra said.

The Ministry of Earth Sciences, which oversees IMD, has constituted a high-powered panel of experts drawn from IMD, the Indian Institute of Tropical Meteorology in Pune, the National Centre for Medium Range Weather Forecasting, and other agencies to deliberate on the use of AI in forecast modelling.

Internally, IMD has also formed a panel to work on AI-driven forecasting and explore broader applications of AI.

Meanwhile, the department is using AI to develop a ChatGPT-like communication tool, and the multilingual weather forecasting app Bhashini already employs AI to translate forecasts into regional languages.

"Not only that, we have also partnered with a host of private and public research institutions such as Indian Institutes of Technology, Indian Institutes of Management, and other universities to jointly develop AI-based models and applications," Mohapatra told *Business Standard* recently.

He added that IMD is studying various AI models and exploring ways to adapt those used by European agencies such as the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Currently, IMD is using AI for smaller, day-to-day tasks such as calculating heat indices and tracking the paths of tropical cyclones, among other applications.

"But these are very small uses of AI," Mohapatra admitted. "An all-India, global, or even regional AI-based model for predicting rainfall, temperature, wind speed, or any other parameter — comparable to what we achieve through physical models — has not yet been developed. But it is under development by the ministry."

"PEOPLE ARE STILL EXPERIMENTING WITH AI, AND, MOST IMPORTANTLY, FOR NOW, IT CANNOT REPLACE ALL EXISTING PHYSICAL MODELS"

Mrutyunjay Mohapatra
Director-General, IMD

He added that there is no firm time frame for when a fully AI-based weather forecasting model will be ready in India, only that the work is ongoing.

According to Mohapatra, this limitation is not unique to India. Globally too — whether in Europe or China — no country or agency has yet fully relied on AI to develop weather forecasting models. "It has not replaced physical models anywhere so far," he pointed out.

"People are still experimenting with AI, and, most importantly, for now, it cannot replace all existing physical models," Mohapatra said.

He cautioned that AI-based forecasting models are not always completely reliable and sometimes show lower accuracy than physical models.

Mohapatra cited recent tropical cyclone Montha as an example. He said IMD saw the AI model of ECMWF. However, the track forecast of IMD did not depend upon any individual model. "We are checking the performance of different models. It will take time," Mohapatra said.

"There are many such examples of AI not performing uniformly well in all aspects. Especially for extreme weather events, our experience shows that AI has not been able to capture their intensity accurately," he said. "So yes, there are still many issues with AI, though it continues to evolve both in India and globally."

"If you ask whether it will rain or not at a particular place, AI may perform well," he said. "But if you ask whether it will rain heavily or not, AI will fail."

TECHDIGEST mybs.in/tech

Ray-Ban Meta glasses to be sold on Amazon, Flipkart

Meta has announced that its Ray-Ban Meta Gen 1 smart glasses will soon be available in India through Amazon, Flipkart, and Reliance Digital, starting November 21. Priced from ₹29,900, the glasses are already available for purchase via the official Ray-Ban website.

Google Pixel Watch 4 goes on sale

Google's Pixel Watch 4 is now available for purchase in India. Launched alongside the Pixel 10 series, the smartwatch is priced at ₹39,900 onwards and comes in 41mm and 45mm dial options. Buyers will also receive a six-month Fitbit Premium subscription at no additional cost.

ॲक्वा लाईन मेट्रोमुळे बेस्टचे प्रवासी घटले!

प्रवाशांना बेस्टकडे वळवण्यासाठी अधिक गाड्या सोडण्याच्या विचारात प्रशासन

पूनम पोळ/ मुंबई : मुंबईमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये ॲक्वा लाईन मेट्रोची एंट्री झाल्यामुळे बेस्टच्या प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. विशेषतः कमी अंतराच्या मार्गांवरील प्रवाशांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, बेस्ट प्रशासन प्रवाशांना पुन्हा बेस्ट बसकडे वळवण्यासाठी अधिकच्या गाड्या सोडण्याच्या विचारात असल्याची माहिती बेस्ट अधिकाऱ्यांनी दिली.

मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर व्हावा, यासाठी वाहतूक व्यवस्थेमध्ये अनेक सुधारणा केल्या जात आहेत. मुंबईमध्ये ॲक्वा लाईन ८ ऑक्टोबरपासून पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली आहे. यापूर्वी १० मेपासून बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ते आचार्य अत्रे चौक (वरळी) या दरम्यान वाहतूक सुरू झाली होती. या वाहतुकीमुळे गेल्या महिन्यात प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे बेस्टचे आर्थिक नुकसान होत आहे. यासाठी बेस्ट प्रशासनाच्या वतीने बेस्ट प्रवाशांना बेस्टकडे पुन्हा वळविण्यासाठी अभ्यास सुरू आहे. आणि येत्या काही दिवसात बेस्टच्या अतिरिक्त बसेस सोडण्यात येणार आहेत.

दक्षिण मुंबईतील ५० टक्के प्रवासी घटले

मेट्रो-३ मुळे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते नरिमन पॉइंट/कफ परेड मार्गावर बेस्टची प्रवासी संख्या ५० टक्क्याने घटली आहे. अशा परिस्थितीत बेस्टने फीडर बस सेवांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून या आर्थिक अडचणीत असलेल्या उपक्रमाला अधिक प्रवासी आणि महसूल मिळू शकेल. अशी माहिती बेस्ट अधिकाऱ्यांनी दिली.

बेस्टमध्ये सध्याचा बदल

बेस्ट प्रशासनाने ५ नोव्हेंबर रोजी २३ प्रमुख मार्गांवर कनेक्टिव्हिटी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी वातानुकूलित बसेसच्या ताफ्यात वाढ केली आहे. या बदलांचा भाग म्हणून, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (कफ परेड) आणि सीएसएमटी दरम्यान 'ए-१०१' ही नवीन वातानुकूलित सेवा सुरू करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, आठ मार्गांवर केवळ वातानुकूलित बसेस चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ॲक्वा लाईनमुळे सुखकर प्रवास

बससाठी थांब्यावर बराच वेळ थांबावे लागत होते. गर्दीतून धक्काबुक्की करून प्रवास करावे लागत होते. परंतु ॲक्वा लाईन सुरू झाल्यापासून प्रवास सुखकर होत आहे. मंत्रालय ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंतचा प्रवास सुखकर होत आहे, असे अनिल सौदाळे या प्रवाशाने सांगितले.

सिटीफ्लो फीडर बससेवेमुळेही बेस्ट डबघाईत

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने सिटीफ्लो या खासगी कंपनीसोबत मिळून मेट्रो लाईन ३ (ॲक्वालाईन) साठी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स आणि वरळी स्टेशनवर विशेष फीडर बस सेवा सुरू केली आहे. मात्र, मुंबईकरांची सेकंड लाईफलाईन असलेल्या बेस्ट बसला जाणूनबुजून डावलले आहे. त्यामुळे बेस्टच्या महसुलातील घट वाढली आहे. परंतु, प्रवाशांना परत आणण्यासाठी अभ्यास सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

गायींच्या पालनपोषणाचा प्रश्न गंभीर!

सहा महिन्यांपासून अनुदान थकीत; गोशाळांची दमछाक

मुंबई : राज्यातील नोंदणीकृत गोशाळांना देशी गायींच्या (गोमाता) संगोपनासाठी देण्यात येणारे अनुदान गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडल्यामुळे गोशाळा चालकांसमोर मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. एकीकडे वाढत्या महागाईमुळे गायींचे पालनपोषण करणे कठीण झाले आहे, तर दुसरीकडे शासनाकडून मिळणारे तुटपुंजे अनुदानही वेळेवर मिळत नसल्याने 'गोमाते'चा सांभाळ करताना गोशाळांची दमछाक झाली आहे.

राज्यातील देशी गायींना 'गोमाते'चा दर्जा दिल्यानंतर त्यांच्या संगोपन, संवर्धन आणि पालनपोषणासाठी राज्य शासनाकडून आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार, नोंदणीकृत गोशाळांना प्रति गाय दररोज ५० रुपये इतके परिषोषण अनुदान दिले जाते. राज्यात एकूण १०६८ गोशाळा आहेत. मात्र गोशाळांकडे नोंदणी केलेल्या गोशाळांना अनुदान दिले जाते. गोवंश हत्याबंदीमुळे भाकड व अनुत्पादक गायींना गोशाळांमध्ये दाखल केले जाते. तसेच, मोकाट जनावरे आणि पोलीस कारवाईनंतर सुटका केलेल्या जनावरांचेही संगोपन गोशाळा करतात. मात्र, शासनाकडून केवळ नोंदणीकृत गोशाळांतील देशी गायींसाठीच अनुदान दिले जाते, इतर पशुधनासाठी कोणताही आधार मिळत नाही. शासनाने राज्यातील गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ आणि गोरक्षण संस्थांना बळकट करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला होता.

गोमातेचा दर्जा दिला, पण चाऱ्यासाठी पैसे नाहीत! गोशाळांना जानेवारी ते मार्च २०२५ या तीन महिन्यांचे अनुदान मिळाले. मागील सहा महिन्यांपासून अनुदान रखडल्याने गोशाळांना गोमातेचा सांभाळ करताना खूपच कसरत करावी लागत आहे. पूर्वी समाजातील देणगीदारांकडून गोशाळांना मदत मिळत होती. मात्र शासनाकडून अनुदान मिळण्याची घोषणा झाल्यानंतर देणगीदारांनी हात आखडता घेतला आहे. आता सरकारचे अनुदान वेळेत नाही आणि देणगीदारांकडूनही मदत नाही अशी गोशाळा चालकांची कोंडी झाली आहे. देशी गायींना राज्य मातेचा दर्जा दिला, पण चाऱ्यासाठी पैसे मिळत नाही हे खेदाची बाब आहे.

- दत्ता रघुनाथ पाहारे, अध्यक्ष माता इंद्रायणी गोशाळा, मानधनी ता. जिंतूर, जि. परभणी

पुरवणी मागण्यांच्या मंजुरीनंतर अनुदान! १ ते ४ डिसेंबरदरम्यान पात्र ४६९ गोशाळांना एक महिन्याचे अनुदान देण्यात आले आहे. पाच महिन्यांचे अनुदान शिल्लक आहे. नागपूर येथे डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात मंजूर झाल्यानंतर पुढील अनुदान देण्यात येईल. तसेच १९० गोशाळांना शेडसाठी अनुदान देण्यात आले आहे. त्यामध्ये ५० गोवंश असलेल्यांना १५ लाख, १०० हून अधिक असलेल्यांना २० लाख आणि २०० हून अधिक असलेल्यांना २५ लाख रुपये अनुदान वाटप केले आहे.

- शेखर मुंदडा, अध्यक्ष राज्य गोसेवा आयोग

आयुष प्रणाली म्हणजे जगण्याची नवी प्रेरणा!

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचे प्रतिपादन

मुंबई : गोव्यातील अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था येथे सुरू झालेले समग्र कर्करोग उपचार व संशोधन केंद्र हे या विचाराचे सशक्त उदाहरण आहे. या केंद्रातील रुग्णांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यांतील विश्वास आणि चेहऱ्यावरील शांतता पाहून जाणवले की, आयुष प्रणाली फक्त उपचार नाही, ती जगण्याची नवी प्रेरणा आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष मंत्रालय, प्रतापराव जाधव यांनी केले.

ते म्हणाले की, "शस्त्रक्रिया, किमोथेरपी किंवा किरणोपचारानंतर जेव्हा शरीर थकून जाते, तेव्हा योग, ध्यान, आयुर्वेद व निसर्गोपचार रुग्णाला नवसंजीवनी देतात. आहारातील बदल, ऋतूनुसार जीवनशैली, औषधी वनस्पतींचा वापर आणि मानसिक स्थैर्य या सर्व गोष्टी मिळून रुग्णाला उपचारांचा त्रास कमी करण्यास आणि मनःशांती पुन्हा मिळवण्यास मदत करतात."

"आज राष्ट्रीय कर्करोग जनजागृती दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे की उपचार म्हणजे नेमकं काय? फक्त औषधं, चाचण्या आणि शस्त्रक्रियांचा संच का, की त्यात रुग्णाचं संपूर्ण जीवन, मन आणि आत्मा यांचाही विचार असायला हवा? माझ्या मते, आरोग्याचा खरा अर्थ म्हणजे शरीर, मन आणि समाज यांचं संतुलन. आणि म्हणूनच समग्र उपचार पद्धती (इंटीग्रेटिव्ह ऑनकोलॉजी) ही आपल्या आरोग्य व्यवस्थेतील एक अत्यंत महत्त्वाची पायरी ठरत आहे," असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेत दहिसरच्या 'विद्या मंदिर'चा डंका

मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानविषयक दृष्टिकोन जागृत व्हावा, म्हणून गेल्या १० वर्षांपासून महाराष्ट्र विज्ञान परिषदेकडून विज्ञान एकांकिका स्पर्धेचे आयोजन केले जात आहे. या स्पर्धेच्या राज्यस्तरीय अंतिम स्पर्धेत शालेय गटात मुंबई दहिसरच्या 'विद्या मंदिर' शाळेच्या 'अजबाई' एकांकिकेने बाजी मारली.

तेजस्विनी खताळ ठरली सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री

मानवी जीवनाला विशेषतः वैद्यकीय क्षेत्राला वरदायी ठरलेल्या 'रेडियम'चा शोध लावणाऱ्या मेरी क्युरी यांच्यावर जीवनावर आधारित 'अजबाई' या एकांकिकेने जागतिक मराठी रंगभूमी दिनाच्या पूर्वसंध्येला वाशीच्या साहित्य संस्कृती सभागृहात पारितोषिकांची लयलूट करत प्रथम क्रमांकाचा मान पटकावला. सर्वोत्कृष्ट एकांकिका, सर्वोत्कृष्ट लेखक, सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक, सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री, सर्वोत्कृष्ट प्रकाशयोजना, सर्वोत्कृष्ट संगीत, सर्वोत्कृष्ट नेपथ्य अशी सर्व विभागाची पारितोषिके जिंकत सभागृहात विद्या प्रसारक मंडळाच्या 'विद्या मंदिर'ने आपल्या एकांकिकेचा ठसा उमटविला. मेरी क्युरीची भूमिका करणाऱ्या तेजस्विनी खताळ हिने आपल्या सहज सुंदर अभिनयाने उपस्थित सर्व प्रेक्षक, परीक्षक आणि नाट्यक्षेत्रातील जाणकारांची मने जिंकली.

निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाचा नकार

एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक

मुंबई : जागतिक वारसा असलेल्या मुंबई एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक काही तासांवर आलेली असताना, आता वेगळ्याच वळणावर पोहोचली आहे. उच्च न्यायालयाने निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मात्र ३ ऑक्टोबरपर्यंत सभासद झालेल्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्याचा धर्मादाय उपायुक्तांचा निर्णय न्यायमूर्ती रेवते मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. निवडणूक प्रक्रियेबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांनीच निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मुंबई एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेल्या माजी खासदार व ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर तसेच माजी खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांचे गट आमनेसामने आहेत. राजकीय शिरकाव आणि सभासदांचा वाढलेल्या आकड्यामुळे हे प्रकरण धर्मादाय आयुक्तांकडे गेले होते.

Worked as CIA mole in Iran for over 25 yrs: Fake BARC scientist

In his statement, accused allegedly says he was planted to sabotage Iran's nuclear mission; the US agency paid a substantial sum in dollars, he adds

Ashish Singh
MUMBAI

The probe into the arrest of two brothers impersonating Bhabha Atomic Research Centre (BARC) scientists has taken a sudden international turn. During interrogation, the primary accused, Akhtar Hussaini Qutbuddin Ahmed, 60, claimed that he operated as a covert asset of the United States' Central Intelligence Agency (CIA) for over 25 years, under multiple assumed identities.

FPJ EXCLUSIVE

In his statement, Akhtar disclosed he allegedly had a clandestine liaison with CIA-linked operatives in Abu Dhabi during 1991-92. Officials familiar with the interrogation records stated that Akhtar told investigators that the meeting was arranged through intermediaries associated with a "Western energy-research consortium". He allegedly posed as an Indian nuclear physicist specialising in atomic energy research and working on dual-use technologies with potential relevance to thermonuclear weapons development.

During this encounter, Akhtar claimed he presented his proprietary PWR-based (pressurised water reactor) fusion reactor prototype blueprint to the CIA operative, who in turn, offered him a "new deal". The operative allegedly provided a deliberately altered reactor blueprint, containing altered isotopic compositions and fusion-core configurations, and instructed Akhtar to share the changed design with Iranian scientific entities as his own work. The accused claimed that he was paid a substantial sum in US dollars to execute the operation.

He further revealed that the CIA allegedly targeted an Iranian diplomat stationed at the Abu Dhabi embassy, believed to be operating under official cover for Iran's security apparatus. The diplomat was reportedly compromised through a calibrated honey-trap operation by the CIA, which, according to Akhtar, enabled the agency to extract classified intelligence on Iran's uranium-enrichment programme, reactor-grade material procurement networks and associated nuclear research infrastructure.

To take forward the high-profile espionage plan, the accused was reportedly tasked by the CIA to establish and maintain controlled contact with the compromised diplomat, facilitating indirect outreach to Iran-based research panels affiliated with Iran's Atomic Energy Organisation.

Under this coordinated arrangement, Akhtar claimed to have travelled to Tehran, where he engaged with Iranian nuclear researchers and presented the PWR-fusion reactor prototype design blueprint for technical review.

During these scientific exchanges, however, Akhtar was unable to substantiate the theoretical segment concerning isotopic chemical equilibrium and plasma-stabilisation sequences within the modified reactor framework.

The inconsistencies in his explanations exposed structural and computational flaws, causing the operation to collapse prematurely. Following his exfiltration to Abu Dhabi, Akhtar claimed that the CIA inducted him into a long-term Iran-centric infiltration grid, designed to cultivate deep-cover assets for prospective deployment within Iran's nuclear and defence research ecosystem.

Though the investigators acknowledged the sensitivity of the disclosures made by the accused, but maintained a calibrated scepticism. Akhtar's detailed narrative may include elements of fabrication or psychological conditioning, they doubted.

According to Akhtar's recorded statement, following his induction into the CIA's operational programme, he continued to maintain covert communication and undertook multiple visits to the Iranian embassies in Delhi and Mumbai as well as other diplomatic and research-linked facilities considered sensitive by security agencies. He reportedly remained in periodic contact with several diplomats and intelligence intermediaries, both Iranian and foreign, under the guise of scientific collaboration.

Akhtar further claimed that he frequently travelled to Dubai between 1992 and 1998 where he held follow-up meetings with CIA operatives before being dispatched to Iran along with a designated handler. His objective was to obtain intelligence on Iran's nuclear development roadmap and to introduce a deliberately modified reactor blueprint designed to misdirect Iranian nuclear research entities. He allegedly received substantial payments for these assignments, which were channeled through Iran-based intermediaries and CIA-linked financial conduits.

Akhtar claimed that during his intermittent visits to Iran, he was relocated under a CIA-supervised technical cover project in Tehran, where he operated within a dual-layered intelligence framework; one focused on tracking regional nuclear-material trafficking networks and another on mapping collaborative exchanges between Middle Eastern research institutions and Iranian defence-linked scientists.

He alleged that under this assignment, he coordinated with US field assets to compile technical intelligence dossiers detailing uranium procurement, reactor-grade isotopic material flow and the movement of research personnel across Iraq, Syria and Iran.

TIMELINE

1991-92

Akhtar allegedly had a clandestine liaison with CIA-linked operatives in Abu Dhabi, UAE

He claimed he presented his fusion reactor prototype blueprint to a CIA operative

The latter allegedly provided a modified blueprint to mislead Iranian entities

1992-98

Akhtar claimed he held several follow-up meetings with the operatives in Dubai

He was later dispatched to Iran along with a designated handler

India's first mangrove park soon in Gorai: Goyal

FPJ News Service
MUMBAI

Mumbai's Gorai Mangrove Park will soon open to the public, with the Dahisar Mangrove Park to follow, announced Piyush Goyal, North Mumbai MP and Union Minister, on Thursday. Costing Rs110 crore, these projects aim to redefine North Mumbai's green identity. Since Goyal's election in May 2024, project implementation has accelerated, with regular reviews, the latest in early November 2025.

"Projects like the Gorai Mangrove Park — India's first dedicated mangrove-themed urban biodiversity park — and the Dahisar Mangrove Park will not only boost sustainable tourism but also strengthen the city's natural defenceline against calamities such as cyclones and soil erosion," Goyal observed.

The Rs 30-crore Gorai Mangrove Park, developed by the state's mangrove cell, features an 800-metre eco-sensitive elevated wooden trail through mangrove forests for non-intrusive experiences. It includes a mangrove interpretation centre with digital exhibits, models, and interactive displays on mangroves' role in biodiversity, coastal resilience, and carbon sequestration. Observation decks, educational signage, and eco-friendly visitor facilities complete the low-impact design.

The Rs 80-crore Dahisar Mangrove Park, spanning 30 hectares, blends adventure, awareness, and education under the theme "Attract, Engage, and Educate." It offers a unique experience of Mumbai's mangrove expanse alongside urban vibrancy, promoting eco-tourism. Both parks align with Goyal's vision to transform "Uttar Mumbai to Uttam Mumbai," fostering nature connection, inspiring youth, and creating local jobs through conservation-based eco-tourism.

City Khojas celebrate Mamdani's triumph, cite ancestral roots

A community member, Mamdani's father Mahmood was born in Mumbai; his great-grandfather Alibhai was Khoja Jamaat's Dar es Salaam branch president

Manoj Ramakrishnan
MUMBAI

While the country celebrates Zohran Mamdani's historic win in the New York City's mayoral polls for his Indian origin, the Khoja community, of which he is a member, in Mumbai has a special reason to cheer as his family has an association with the city. The term Khoja is derived from the Persian word 'Khwajeh', which means noble.

When Mamdani won the Democratic Party's primary contest against Andrew Cuomo, the Khoja Shia Ithna-Asheri (KSIA) diaspora, including community members from the city, launched a 'Khojas for Zohran' social campaign to root for him.

Mamdani's father, Mahmood Mamdani, was born in Mumbai, where the family had migrated from Hadiyana in Gujarat's Kathiawar region. According to KSIA Jamaat, Mumbai, Mamdani's great-grandfather, Mulla Kermalli Alibhai Ratansi, who passed away in 1958, served as the president of the Dar es Salaam branch of the association between 1950 and 1952. Ratansi migrated to East Africa at the age of 16, built a successful business and later led philanthropic projects. One of his children, Yusuf, was Zohran's grandfather, according to the community.

As a predominantly trading and business community, Khojas are reluctant to align themselves to any political movements. Mamdani's win, therefore, has been received with low-key reactions. "We are a quiet community, which believes in humanity and ideas that were part of Mamdani's campaign such as immigrant's rights, affordable rents, fare-free commuting and public child care," said Ali Akbar Shroff, KSIA Jamaat, Mumbai president.

The long name distinguishes the community from the larger groups with which they split after theological disputes. Khojas trace their origin to conversion of Hindus in Sindh, Gujarat and Punjab to Islam from the 11th century onwards. The group had its beginnings in the Satpanth Ismaili tradition, with earlier connections to the Swaminarayan Hindu sect.

Under the influence of a succession of religious leaders called Pirs and Dais, including Pir Sadardin, they evolved into the contemporary group. They consider themselves as descendants of the Lohana caste. Shroff pointed out that his grandfather carried the name, Madhavji Hirji. After a series of ideological disputes, splits and court cases later, the community emerged as the 'Khoja Shia Ithna-Asheri' in the late 19th century.

Haji Parekh, a Jamaat member, stated that they follow a democratic process to elect their Jamat, the administrative body that holds regular elections to elect its leaders. The Mumbai unit was established in 1896-97 and registered in 1901 and the polls were held the same year. One of the more famous Khojas is Mohamed Ali Jinnah, the founder of Pakistan.

IN NUMBERS

Khoja Shia Ithna-Asheri estimated population

1,25,000
Worldwide

30,000
Live in India

18,000 to 20,000
City count

Late 19th century
Sect reached Mumbai

1901
Community builds first mosque in city